भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1176

30 जुलाई, 2024 को उत्तर के लिए नियत

शून्य कार्बन उत्सर्जन

1176. डॉ. राजेश मिश्रा:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत में हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से अपनाने एवं विनिर्माण (फेम इंडिया)-3 योजना के अंतर्गत देश में दो, तीन एवं चार पहिया वाहनों के इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी बढ़ाकर कार्बन ईंधन पर निर्भरता कम करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इन वाहनों के लिए अलग से बजटीय आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए देश के सभी पेट्रोल एवं डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने के लिए कोई समय-सीमा तय की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए रोडमैप का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)

(क) और (ख): वर्तमान में भारी उद्योग मंत्रालय देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण में तेजी लाने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है:

i. 1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2024 तक की 4 महीने की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपये के परिव्यय से इलेक्ट्रिक वाहन संवर्धन स्कीम-2024 (ईएमपीएस), जिसमें ई-दुपहिया और ई-तिपहिया वाहनों के ख़रीदारों को आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

ii. 25,938 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय से ऑटोमोबिल और आटो कंपोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई-एएटी)। इस स्कीम के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों को आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है जिनमें इलेक्ट्रिक दुपहिया, इलेक्ट्रिक तिपहिया, इलेक्ट्रिक चौपहिया वाहन, इलेक्ट्रिक बसें और इलेक्ट्रिक ट्रक शामिल हैं।

iii. 18,100 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय से उन्नत रसायन सेल विनिर्माण के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई-एसीसी)।

iv. वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं से निवेश आकर्षित करने और भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रमुख विनिर्माता के रूप में बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक यात्री कार विनिर्माण संवर्धन स्कीम।

(ग): जी, नहीं।

(घ): उक्त (ग) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

****